

कोविद-19 (महामारी) का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव Impact of COVID-19 (Pandemic) on Indian Economy

Date of Paper Submission: 20/04/2020, Acceptance Date: 22/04/2020, Publication Date: 29/04/2020



हरि राम मीना

सहायक प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय
दौसा, राजस्थान, भारत

सारांश

पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है। भारत में इसका असर अधिकतर सेक्टर पर देखा जा सकता है। खासकर रियल एस्टेट, एयरलाइन्स, ज्वेलरी और ऑटो सेक्टर पर सबसे ज्यादा है। इन सेक्टर को वापसी में समय लगेगा। टेलिकॉम, मोबाइल, फूड, आईटी, एफएमसीजी, जैसे सेक्टर में मंदी का असर कम होने की संभावना है। निर्माणकार्य, पॉवर, ऑटो पीवी जैसे सेक्टरों की रिकवरी ज्यादा तेज नहीं होगी ये सेक्टर उन अहम सेक्टर से जुड़े हैं जहाँ हालात खराब हैं। कोरोना के चलते वैश्विक मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि दुनिया को अर्थव्यवस्था के संकटों से जूझना पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए कुछ राहत की खबर है। अगर भारत इस वायरस को यहीं पर रोकने में कामयाब हो जाता है और लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो यहां वैश्विक मंदी की मार अपेक्षा कम हो सकती है। संभव है कि भारत जैसे देश एक तिमाही के बाद इस मंदी से निकल जाए। भारत में वर्तमान में लॉक डाउन में शटर डाउन जैसे हालात हो गये हैं। कारोबार ठप है, उद्योग बंद है, कारोबारी घर बैठे हैं और मंदी के साथ बेरोजगारी बढ़ने का संकट मंडरा रहा है। यह शोध पत्र कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा तथा कोरोना के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करेगा।

The whole world is currently battling the corona virus. In India, its impact can be seen on most sectors. Especially in real estate, airlines, jewelery and auto sector is the highest. These sectors will take time to return. In sectors such as telecom, mobile, food, IT, FMCG, the impact of the slowdown is likely to decrease. The recovery of sectors like construction work, power, auto PV will not be very fast, these sectors are connected to the important sectors where the situation is bad. Fears of global slowdown due to Corona are being expressed. It is being said that the world will have to grapple with the crisis of the economy. There is some relief news for countries like India. If India manages to stop this virus here and the lockdown does not last long. So here the expectation of global recession may be less. It is possible that a country like India gets out of this recession after one quarter. In India, there has been a shutdown like situation in lock down. Business is at a standstill, industry is closed, businessmen are sitting at home and there is a crisis of increasing unemployment with recession. This research paper will help to study the effect of Corona virus on the Indian economy and will explain the economic impact of Corona on various sectors.

मुख्य शब्द : वैश्विक मंदी, बैरल, अंतरराष्ट्रीय बाजार, क्रूड आयल, लॉक डाउन, एविएशन सेक्टर, डीजीसीए, दिहाड़ी, खुदरा कारोबार, मध्यम, लघु, एवम सूक्ष्म उद्योग, अर्थव्यवस्था, गंभीर मंदी, मुद्रा स्फीति, आर्थिक विकास दर, फाइनेंस सर्विस, सूचना प्रौद्योगिकी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वर्क फ्रॉम होम, निवेशकों, सोशल डिस्टेंस।

Keywords : Global Recession, Barrels, International Markets, Crude Oil, Lock Down, Aviation Sector, DGCA, Daily Wages, Retail Business, Medium, Small, Micro And Small Industries, Economy, Severe Recession, Inflation, Economic Growth,

Finance Service, Information Technology, Tourism, Hospitality, Work From Home, Investors, Social Distance

प्रस्तावना

कोरोना वायरस का कहर दुनिया पर इस तरह भारी पड़ेगा, शायद किसी ने सोचा होगा। यह समूची मानवता के लिए गंभीर चुनौती से कम नहीं है। इसने अमरीका, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। जिसका असर वर्षों तक नजर आयेगा कई वर्ष इसकी भरपाई में ही लग जायेगे। विशेषज्ञों का मानना है की बजट में अब मेडिकल सुविधाओं व खाद्य आपूर्ति का विशेष ध्यान रहना होगा। शहरी क्षेत्रों में कोरोना की वजह से बेरोजगारी दर बढ़कर 30.9 फीसदी हो जाएगी। जबकि ओवरऑल बेरोजगारी की दर 23.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी के साप्ताहिक सर्वे के आकड़ों के अनुसार मध्य मार्च में 8.4 फीसदी रहने वाली बेरोजगारी दर 5 अप्रैल तक बढ़ कर 23 फीसदी हो गई। भारत के सांख्यिकीविद प्रनब सेन के मुताबित एक अनुमानित आधार पर पिछले दो सप्ताह (25 मार्च 2020 से) में करीब 50 मिलियन यानि पांच करोड़ लोग बेरोजगार हुये है। संपति सलाहकार कंपनी जेएलएल की रिपोर्ट के मुताबित देश में आवासों की बिक्री जनवरी से मार्च की अवधि में 29 फीसदी कम हो गई। शहरों में इस दौरान 24541 आवास बिके है जबकि 3.7 लाख करोड़ आवास बनकर खड़े है।

अध्ययन का उद्देश्य

यह शोध पत्र कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने में मदद करेगा तथा कोरोना के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को स्पष्ट करेगा।

कोरोना वायरस का बैंकों व उद्योगपतियों की सेहत पर प्रभाव

एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत में कोरोना महामारी के चलते आर्थिक मंदी से देश में 2020 के दौरान बैंकों के गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) अनुपात में 1.9 फीसदी और ऋण लागत अनुपात में 1.3 फीसदी की बढ़ोत्तरी का अनुमान है। कोरोना वायरस के चलते देश के अरबपतियों पर भी असर दिखने लग गया है। हरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारतीय अरबपतियों को भारी नुकसान हुआ है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 300 मिलियन डॉलर प्रतिदिन गिरकर 31मार्च 2020 को 48 बिलियन डॉलर तथा गौतम अदानी की सम्पति इस दौरान (37 फीसदी) छह अरब डॉलर व उदय कोटक को चार अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है।

भारत में 22 साल के निचले स्तर पर आया कच्चा तेल

भारत में कोविड-19 महामारी का असर कच्चे तेल के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के चलते भारत में 30 फीसदी फैक्ट्रीयों में उत्पादन बंद है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में 40 फीसदी की कमी आई है। तथा पट्रोल व डीजल की बिक्री में ऐतिहासिक गिरावट आने के कारण तेल रिफिनारियों के

बंद होने का खतरा हो गया है। हवाई जहाज के इंधन में तो 90 फीसदी की गिरावट आई है। ग्लोबल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 22 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है। भारत में एक बैरल की कीमत 1700 के करीब आ चुकी है। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है इस लिहाज से एक लीटर क्रूड आयल की कीमत 10.69 रुपए प्रति लीटर होती है। कोरोना वायरस की वजह से दुनियाभर के देशों में लॉक डाउन किया गया जिसकी वजह से डिमांड में भारी कमी आयी और कच्चे तेल की कीमत कम हुई है।

कोरोना वायरस (महामारी) का भारतीय एविएशन क्षेत्र पर प्रभाव

देश में करीब करीब सभी सेक्टरों में मंदी का असर दिख रहा है। लेकिन लॉक डाउन की वजह से जिस सेक्टर को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है वह देश का विमानन सेक्टर ट्रैवेलर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन इंडिया के अनुमान के मुताबित एविएशन सेक्टर को कुल 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जिसमें सिर्फ भारतीय कंपनी को 70-80 हजार करोड़ का नुकसान होगा। डीजीसीए के मुताबित हर दिन 350-400 करोड़ रुपए का बिजनेस होता थाद्यलेकिन उड़ाने निरस्त होने के कारण हर दिन 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आईसीआईसीआई सिक्वोरिटीज की रिपोर्ट के मुताबित इंडिगो को सबसे ज्यादा 5494 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जबकि स्पाइस जेट को करीब 1412 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जबकि एयर इंडिया को 30 से 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है।

कोरोना वायरस का खुदरा कारोबारियों व मध्यम,लघु उद्योगों पर प्रभाव

कोरोना वायरस के बाद होने वाले लॉक डाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित दिहाड़ी पर काम करनेवाले लोग परेशान हुये है। देश की जीडीपी में खुदरा कारोबार का 10 फीसदी हिस्सा है। खुदरा कारोबार में 85 फीसदी खर्चा पहले ही हो जाता है। फरवरी 2020 में इनका कारोबार 50 से 60 फीसदी घट गया व लॉक डाउन के समय पूरी तरह बंद हो गया था द्यवही देश में मध्यम,लघु,एवम सूक्ष्म उद्योग में करीब 6.9करोड़ उधमी है। लॉक डाउन के कारण एमएसएमई की 17 लाख दुकाने बंद हो गई थी। देशभर में छोटीमोटी दुकाने चलाने वाले खुदरा कारोबारियों के सामने भी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। वर्तमान में खुदरा क्षेत्र में देश में 60 लाख लोग कार्यरत है। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है,वो है कारोबार में बना रहना व अपना रोजमरा का खर्चा निकालना है। देश में लॉकडाउन के चलते किराना . मेडिकल के अलावा सभी दुकाने बंद रही है। देश के छोटे दुकानों की आय का 7 से 8 फीसदी हिस्सा किराये में चला जाता है। तथा 8 से 9 फीसदी वेतन भुगतान में चला जाता है। यदि इनके लिए कोई नीति नहीं बना गई तो इनके हालत बदतर होते चले जायेगे द्य कोरोना के चलते आज के समय 90 फीसदी इकाइयां बंद है। उद्योगों और भवन निर्माताओं के अलावा अन्य सेक्टरों में भी

मजदूरों का अभाव देखा जा सकता है। इस को सुधरने में कई महीने लग जाएंगे। देश के 90 फीसदी छोटे उद्योग कर्ज के लिए गैर वित्तीय संस्थाओं के पास जाते हैं। अब ये संस्थाएं खुद ही मुश्किल में हैं। कर्ज मुहैया कराना चुनौती हो गया है।

कोरोना वायरस के चलते अनाज के भावों, छोटी दुकानों व ई-कॉमर्स कंपनियों प्रभाव

कोरोना वायरस के गहराते प्रकोप के चलते घबराहट में लोग दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदारी अपनी जरूरत से ज्यादा करने लगे हैं। वहीं, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से फैक्ट्रीयों में उत्पादन से लेकर, वितरण समेत पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई है जिसमें आटा, दाल, खाद्यतेल और बिस्कुट समेत कई जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। देशभर के किराना स्टोर में पहुँच रहे उपभोक्ता दैनिक उपभोग की वस्तुएं जरूरत से ज्यादा खरीदने लग गये हैं। देश की ज्यादातर अनाज मंडियां बंद हैं और आटा, दाल, और चावल की मीलों समेत खाद्य तेल की फैक्ट्रीयों में कम मजदूरों से काम लिया जा रहा है। लॉक डाउन के दौरान राज्यों की सीमाएं सील होने के कारण एफएमसीजी वस्तुओं के परिवहन को काफी परेशानी आ रही है। हालात में सुधार नहीं हुआ तो जमाखोरी बढ़ने से आने वाले दिनों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी इजाफा हो सकता है। लॉक डाउन के समय अधिकांश ई-कॉमर्स कंपनी सामान की आपूर्ति करने में नाकामयाब रही है। इस संकट में देश को निकालने का श्रेय देशभर में फैली करीब एक करोड़ छोटी बड़ी दुकानों को और तीन लाख से अधिक थोक विक्रेताओं को जाता है। वैश्विक कन्सलटैंसी फर्म केएसए टेक्नोपैक के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनी देशभर में सालाना 2.5 अरब डालर का सामान बेचती है। वर्ष 2019-20 में देश में खाद्य व परचूनी की सालाना बिक्री 550 अरब डालर रही थी। जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों का योगदान मात्र 1.04 फीसदी रहा है। वैसे भी ई-कॉमर्स कंपनियों का नेटवर्क महानगरों तक ही सीमित है और 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी 6 शहरों से आती है। अतः कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में किराना दुकानदारों ने लोगों के घरों में सामान मुहैया करवाया है। कोरोना वायरस के चलते कंज्यूमर उद्योग पर दोहरी मार पड़ रही है। कंपनियों की बिक्री ठप पड़ गई है। आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते एक बड़ा वर्ग खरीदारी करने की हालत में नहीं रहेगा। ऐसे में वित्त वर्ष 2021-22 में इन कंपनियों की आय में 8-39 फीसदी की कटौती का अनुमान लगाया जा सकता है। सरकार के मुताबित भारत की 2.9 लाख करोड़ डॉलर (करीब 220 लाख करोड़ रुपए) की अर्थव्यवस्था में करीब एक तिहाई हिस्सेदारी छोटे व्यवसाय करने वालों की है। यह क्षेत्र 50 करोड़ कामगारों को रोजगार देता है।

ऑटो कंपनियों की बिक्री व विनिर्माण गतिविधियों पर प्रभाव

कोरोना वायरस के चलते ऑटो कंपनियों में मार्च, 2020 में बिक्री 90 फीसदी कम हो गई है। इन कंपनियों की पिछले एक साल से वैसे ही बिक्री के मोर्चे पर गंभीर संकट का सामना कर रही है। देश की सबसे

बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुती की मार्च माह की बिक्री 47 फीसदी तथा हिंदुजा समूह की बिक्री 90 फीसदी कम दर्ज की गई है। कोरोना वायरस का असर देश की विनिर्माण गतिविधियों पर भी दिख रहा है। मार्च महीने में विनिर्माण गतिविधियों की बढ़ने की दर पिछले चार महीनों में सबसे कम रही है। मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा जारी आईएचएस मार्केट भारत विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) घट कर 51.8 रह गया। जो फरवरी में पीएमआई 54.2 दर्ज किया गया था। सूचकांक का 50 से ऊपर रहना गतिविधियों में तेजी व इससे कम रहना गिरावट दिखाता है। यह नवंबर के बाद से सबसे कम बढ़ोत्तरी रही है।

आर्थिक विकास दर पर प्रभाव

कोरोना वायरस के चलते विभिन्न दशों के साथ भारत में भी लॉकडाउन किया गया जिसका असर यह हुआ की भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी के साथ मुद्रा स्फीति के दोहरे जाल में फंस गई है। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर 1.5 से 2.8 फीसदी रहने की उम्मीद है। हालांकि विश्व बैंक ने यह भी अनुमान जताया कि वित्त वर्ष खत्म होने तक भारत की विकास दर 4.8 फीसदी से 5 फीसदी तक बढ़ जाएगी। भारत के लिए अब एक बुरी खबर सामने आयी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने देश की आर्थिक विकास दर (जीडीपी) को घटाकर 3.6 फीसदी कर दिया है। लॉकडाउन को देखते हुए एजेंसी ने जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 2.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। साथ ही मार्च में पूरी होने वाली तिमाही में भी विकास दर महज 4.7 फीसदी रहने का अनुमान है। कोरोना के चलते भारत में कुछ सेक्टरों में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इनमें टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन क्षेत्र में बड़ी गिरावट का अनुमान भी लगाया गया है। वही हेल्थ केयर सेक्टर में कार्यभार बढ़ने की आशंका है। तथा छोटे व्यापारियों के सिमटने का भी खतरा मंडराने की भी बात सामने आ रही है। कोरोना वायरस के चलते व लॉक डाउन के बाद भारत में फाइनेंस सर्विस , सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जैसे क्षेत्रों में बहुत नुकसान नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण वर्क फ्रॉम होम के जरिये काम चालू होने को बताया जा रहा है। आज की परिस्थितियों को देखकर निवेशकों ने अपनी राय भारत को लेकर बदली है। इसी के चलते रूपए में डालर के मुकाबले बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस की कीमत आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारी चुकानी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में करीब एक फीसदी तक घट सकती है। जबकि पहले इसमें 2.5 फीसदी बढ़ोत्तरी का अनुमान था। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुये कहा है कि यदि पर्याप्त आर्थिक मदद का इंतजाम किये बिना आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध बढ़ाया जाता है तो तो यह गिरावट और अधिक हो सकती है।

वर्ष 2020 में ग्लोबल मंदी का भारत पर असर

दुनियाभर की इकॉनोमी में कोरोना वायरस के चलते सुस्ती का अंदेशा जताया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन टूटने के कारण व्यापार में कमी देखने मिल सकती है तथा दुनिया एक बड़ी मंदी की चपेट में जा रही है। यह मंदी 2008-09 की मंदी से भी ज्यादा बड़ी होगी जिसका भुगतान पूरी दुनिया को करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के व्यापार में एक तिहाई से ज्यादा की कटौती देखने को मिल सकती है। संगठन के वैश्विक कारोबार में 13 से 32 फीसदी तक गिरावट आने का अनुमान है। तथा 2021 में विश्व व्यापार में 20-24 फीसदी के रिबाउंड होने के आसार हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की इकॉनोमी को इस साल मंदी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है। इससे विकासशील देशों को ज्यादा मुश्किल होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि भारत और चीन पर इसका असर नहीं होने की उम्मीद है। क्योंकि आज भी भारत में कृषि समेत कई सेक्टर हैं जहां काम पहले की तरह ही चल रहा है। भारत में अकेले कृषि सेक्टर की जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 15 फीसदी है। तथा देश की 50 फीसदी आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है। लॉकडाउन के बाद यहाँ भी काम बंद नहीं हुआ है। तथा देश में करीब 84 लाख टन अनाज का सरप्लस है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है। तथा भारत में लॉकडाउन के बावजूद संगठित क्षेत्र के लोग डेली सिस्टम पर काम कर रहे हैं एवं फार्मा सेक्टर, अनाज प्रोसेसिंग यूनिट्स, में काम लगातार चल रहा है, तथा आईटी सेक्टर में घर से ही काम हो रहा है। इसके अलावा आईटी कंपनी व उद्योगपतियों का भारतीय इकॉनोमी में आज भी विश्वास कायम है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस संकट को सबसे भयानक संकट बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर में 200 करोड़ लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर उभरती और विकाशील अर्थव्यवस्था में हैं और ये विशेष रूप से संकट में हैं। भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत है, इनमें से करीब 40 करोड़ श्रमिकों के सामने गरीबी में फंसने का संकट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने (आरबीआई) ने कोरोना वायरस संकट को भविष्य पर मंडरा रहे काली छाया जैसा बताया है। केन्द्रीय बैंक ने गुरुवार अप्रैल, 09, 2020 को अपनी मौद्रिक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना के चलते लॉक डाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस महामारी से पहले अर्थव्यवस्था के 2020-21 में मंदी से उबरने की आशा जगी थी। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस संकट का वास्तविक नतीजे इससे निपटने की गति और आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा।

निष्कर्ष

कोरोना वायरस के चलते भारत में लॉक डाउन हुआ तथा लॉक डाउन के चलते लोगों की आय पर भी

असर हुआ है। आय घटने से मांग भी प्रभावित होगा जिससे बाजार को बंद के दौरान व आगे भविष्य में भी खतरा बना रहेगा। देश में जीएसटी कलेक्शन करीब 12 से 14 फीसदी की दर से बढ़ रहा था लेकिन कोरोना वायरस ने इसकी कमर तोड़ के रख दी है। हालात इतने खराब हैं कि मार्च 2020 में जीएसटी कलेक्शन इस बार जीएसटी कलेक्शन मार्च 2019 के भी बराबर नहीं पहुंचा है। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना मार्च होने के कारण इस बार जीएसटी कलेक्शन की इसी महीने की उम्मीद थी लेकिन अकेले राजस्थान को 950 करोड़ व मध्य प्रदेश को 500 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो नकारात्मक 10 फीसदी दर को बताती है। आर.बी.आई.को बैंक के तीन महीने के मोरटोरियम को छह महीने के लिए बढ़ा देना चाहिये। तथा एनबीएफसी को भी बैंकों की तरह राहत मिलनी चाहिए। कोरोना वायरस से उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को छह महीने तक कारोबारियों को ब्याज में छूट व बिजली के फिक्स चार्ज को पूरी तरह माफ तथा अगले छह महीने तक कोई एनपीए घोषित नहीं किया जाए। इसके अलावा सरकार को सब्सिडी व लेबर पलायन को रोकने की व्यवस्था भी करनी चाहिए व सभी बैंक को उद्योगों के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट बढ़ानी चाहिए तथा टीडीएस पर ब्याज को पूरी तरह माफ करके उद्योगों के परिचालन की अनुमति मिलनी चाहिए। मंदी की मार झेल रहे रियल सेक्टर पर कोरोना की दोहरी मार पड़ी है इस सेक्टर पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोरोना का असर कितने दिनों तक प्रभावी रहता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। साथ ही कोरोना वायरस के चलते हुये लॉक डाउन के कारण व्यवसाय के सोचने और उसे संचालित करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। आने वाले दिनों में कारोबार का स्वरूप ही बदल जायेगा। कोरोना वायरस ने दुनिया को अभूतपूर्व पैमाने और बहुत तीव्र गति से अपनी चपेट में लिया है। भारत भी इससे बच नहीं सका। अर्थव्यवस्था जो पहले से ही कई त्रिमाहियों से मांग के दबाव, बढ़ती बेरोजगारी, कम औद्योगिक उत्पादन और मुनाफे में कमी से जूझ रही है। उसके लिए आपूर्ति में बाधा एक बड़ा झटका होगा। सरकार को आर्थिक पैकेज और बढ़ाने ने हॉर्गेद्य राजकोषीय और मौद्रिक दोनों मोर्चा पर ठोस कदम उठाने होंगे। विश्व बैंक ने भारत को चेतावनी दी है कि भारत में लंबे समय तक पूरे देश में लॉक डाउन लागू रहने से खराब हालात हो जाएंगे। इस कारण इस वर्ष आर्थिक मंदी देखने को मिल सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. ग्लोबल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट मार्च 29, 2020
2. सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन इंडिया के अनुमान मार्च 28, 2020
3. आईसीआईसीआई सिक्वोरिटीज की रिपोर्ट मार्च 28, 2020
4. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च मार्च 30, 2020
5. संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट मार्च 31, 2020
6. विश्व बैंक रिपोर्ट मार्च 31, 2020

7. मार्केट इकोनॉमिक्स द्वारा जारी आईएचएस मार्केट भारत विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक मार्च 02,2020
8. वैश्विक कन्सलटेंसी फर्म केएसए टेक्नोपैक मार्च,2020
9. बोर्ड ऑफ एग्जिक्युटिव डायरेक्टर्स मीटिंग ,विश्व बैंक अप्रैल,02,2020
10. एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग मार्च,2020
11. हरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के रिपोर्ट मार्च, 2020
12. सेंटर फॉर मोनिटरिंग इंडियन इकोनोमी के साप्ताहिक सर्वे के आकड़े अप्रैल, 2020
13. संपति सलाहकार कंपनी जेएलएल की रिपोर्ट अप्रैल,2020
14. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट अप्रैल, 08,2020
15. केन्द्रीय बैंक ने गुरुवार अप्रैल,09,2020 की मौद्रिक रिपोर्ट
16. विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) की रिपोर्ट अप्रैल, 2020
17. विश्व बैंक की दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट अप्रैल, 2020